Rupali chaubey

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

Qu 1
(a) चकबंदी

- कृषि सुधार के रूप में देखा जाता
- इसके अंतर्गत किसानों की इधर-उधर विखण्डित भूमि एक स्थान पर एकत्रित कर खेती की जाती
- उत्पादन में वृद्धि

(b) प्राथमिक घाटा

- राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राथमिक घाटा प्राप्त
- यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सरकार की वास्तविक राजकोषीय वृद्धि को दर्शाता।

(c) चक्रीय बेरोजगारी
- यह मांग व आपूर्ति में विसंगति के कारण उत्पन्न होती है
- अल्पकालिक होती
- मांग व आपूर्ति समता में वृद्धि कर इसे सरकार द्वारा दूर किया जा सकता।

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका (Mains Answer Sheet)

कौटिल्य एकेडमी

सफलता का प्रवेश द्वार...

(d) राष्ट्रीय आय की मापन प्रणालियाँ।

तीन राष्ट्रीय आय की मापन प्रणाली है -
- उत्पाद संगणना विधि
- आय संगणना विधि
- व्यय संगणना विधि

(e) थोक मूल्य सूचकांक
- मुद्रास्फीति मापने की विधि
- इसके अंतर्गत किसी आधार वर्ष में बनी हुई वस्तुओं सामूहिक औसत मूल्य को दर्शाता
- आधारवर्ष - [illegible]
- इसकी तुलना वर्तमान मूल्य से की जाती व महगाई दर ज्ञात की जाती

(f) सामाजिक प्रगति सिद्धांत

(h) विंडो ड्रेसिंग
- किसी कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ वस्तुओं को छुपा लिया जाता या मिसलेनियस में डाल दिया जाता
- जिससे बुरे नतीजे नहीं दिखते व वार्षिक विवरण आकर्षित दिखता उसे विंडो ड्रेसिंग कहते।
- निवेशक प्रभावित होते हैं।

प्रश्न संख्या | मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका (Mains Answer Sheet) | भारत का नं. 1 संस्थान कौटिल्य एकेडमी सफलता का प्रवेश द्वार...

(G) निर्धनता जाल

- यह एक प्रक्रिया जिसमें गरीब व्यक्ति सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेता है
- रोजगार की तलाश बंद कर देता
- सरकार पर निर्भरता
- अल्पविकसित व विकासशील देशों में देखने को मिलता

(H) ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट

- जब पुराने हवाई अड्डे से दूर किसी नवीन स्थान पर नये हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता है तो उसे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहते है
- यह तब होता जब पुराने एयरपोर्ट पर विस्तार की संभावना न हो।

(I) निर्देशात्मक आयोजन

- मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशिष्टता होती
- सरकार की भूमिका नीति निर्देशक व मार्ग दर्शक
- बाजार की भूमिका प्राथमिक व कार्य करने की स्वतंत्रता होती
- भारत की अर्थव्यवस्था निर्देशात्मक है

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

प्रश्न संख्या | मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका (Mains Answer Sheet)

(J) लक्षित सार्वजनिक प्रणाली
- PDS में 1997 में अपनाई
- लाभार्थियों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है अंत्योदय, BPL, APL
- अलग-2 कीमतों पर खाद्यान्नों का वितरण

(K) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत आयोग की स्थापना की गई
- सांविधिक निकाय
- कार्य => प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त
  - प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना

(L) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- 2 अक्टूबर 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना
- कार्य - दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा
  - कमजोर वर्ग को रियायती दर पर ऋण
  - ग्रामीण बचत को उत्पादन में लगाना

(G) निर्धनता जाल

- यह एक प्रक्रिया जिसमें गरीब व्यक्ति सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेता है
- रोजगार की तलाश बंद कर देता
- सरकार पर निर्भरता
- अल्पविकसित व विकासशील देशों में देखने को मिलता

(H) ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट

- जब पुराने हवाई अड्डे से दूर किसी नवीन स्थान पर नये हवाई अड्डे का निर्माण किया जाता है तो उसे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहते हैं
- यह तब होता जब पुराने एयरपोर्ट पर विस्तार की संभावना न हो।

(I) निर्देशात्मक आयोजन

- मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशिष्टता होती सरकार की भूमिका नीति निर्देशक व मार्ग दर्शक
- बाजार की भूमिका प्राथमिक व कार्य करने की स्वतंत्रता होती
- भारत की अर्थव्यवस्था निर्देशात्मक है

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

(J) लक्षित सार्वजनिक प्रणाली
- PDS में 1997 में अपनाई
- लाभार्थियों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है अंत्योदय, BPL, APL
- अलग-2 कीमतों पर खाद्यान्नों का वितरण

(K) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत आयोग की स्थापना की गई
- सांविधिक निकाय
- कार्य ⇒ प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त
  - प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा

(L) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- 2 अक्टूबर 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना
- कार्य - दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा
  - कमजोर वर्ग को रियायती दर पर ऋण
  - ग्रामीण बचत को उत्पादन में लगाना

भारत का नं. 1 संस्थान
कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

Q. 2(a) स्वयं सहायता समूह क्या है, ग्रामीण विकास में इनके समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

A. स्वयं सहायता समूह 5-20 लोगों का समान पृष्ठभूमि वाले लोगों का समूह, जो अपनी बचत व आपसी सहयोग से आवश्यकताओं की पूर्ति व समस्याओं का समाधान करते। सरकार भी इन्हें प्रोत्साहित करती है।

ग्रामीण विकास में इन समूहों का महत्वपूर्ण भूमिका है किंतु इनके समक्ष कुछ चुनौतियाँ भी है

- वित्त का अभाव => ग्रामीण क्षेत्रों बैंकिंग व्यवस्था की पर्याप्त सुविधा नहीं
- ज्ञान का अभाव => ज्ञान व शिक्षा के अभाव के कारण यह अपने व्यवसाय से लाभ व प्रसार नहीं पाते
- पितृसत्तात्मक विचारधारा => यह विचारधारा महिलाओं को काम करने से रोकती
- कौशल का अभाव => प्रशिक्षण की व्यवस्था न होने से व्यवसाय का सार नहीं
- सुरक्षा की कमी => अपनी बचत से छोटा-मोटा व्यवसाय, हानि होने पर कोई सुरक्षा नहीं

अन्य – जागरूकता का न होना
– आपसी सामंजस्य व समन्वय का न होना

आदि चुनौतियाँ स्वयं सहायता समूह के विकास में नजर आती है अतः सरकार को इन्हें दूर कर इसे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता ताकि ग्रामीण विकास सुनिश्चित किया जा सके।

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

कौटिल्य एकेडमी

Q 2 (b) न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? यह किसानों के लिए किस प्रकार लाभकारी?

A. न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है, MSP की घोषणा भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित फसलों पर बुआई के पहले ही कर दी जाती है।

यह किसानों को निम्न प्रकार से लाभकारी सिद्ध होती

- किसानों को बिक्री की चिंताओं से राहत मिलती
- अधिक उत्पादन से किसानों को एक निश्चित मूल्य प्राप्त होता अर्थात लागत निकल आती
- यह किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित
- किसानों को एक निश्चित राशि समय पर मिल जाने से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति
- किसान गांवों के महाजनों व साहूकारों से बच जाते हैं।
- खाद्यान्नों के मूल्यों में स्थिरता रहती

MSP से किसानों को लाभ होता किंतु इसमें कुछ कमियां सभी फसलों पर लागू नहीं, अलग-2 राज्यों में कीमत अलग-2 आदि को दूर करने की आवश्यकता है।

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका (Mains Answer Sheet)

कौटिल्य एकेडमी सफलता का प्रतीक द्वार...

Que-2(c) समावेशी विकास और इसको प्राप्त करने के उपाय

समावेशी विकास का तात्पर्य भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किये बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

समावेशी विकास को प्राप्त करने निम्नलिखित बिंदु हैं-

- औद्योगिकीकरण के साथ के साथ पर्यावरण संरक्षण व संवर्द्धन
- प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग
- वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा व कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित
- सामाजिक असमानता दूर
- निःशुल्क न्याय
- ऊर्जा के क्षेत्र में नवीनीकरण संसाधनों का प्रयोग
- लोकतांत्रिक मूल्यों (स्वतंत्रता, समानता आदि) प्रचार-प्रसार
- संपत्ति के संकेन्द्रण पर रोक आदि

उपरोक्त के द्वारा ही समावेशी विकास व गांधी जी के सर्वोदय की अवधारणा को साकारित कर सकते हैं।

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका (Mains Answer Sheet)

कौटिल्य एकेडमी

प्र० 2(b) भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में FDI की आवश्यकता को बताइये?

A. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से कहते जब किसी देश में दूसरे देश द्वारा व्यापार विस्तार के लिए निवेश किया जाता है उसे FDI कहते हैं

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में FDI की आवश्यकता को निम्न प्रकार से देखते

FDI की आवश्यकता →

- FDI के आने से अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ता है तथा संतुलन बना रहता
- आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन
- रोजगार सृजन होता है
- विदेशी निवेश आने से बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा जिससे सीधा लाभ उपभोक्ता को मिलता
- आधुनिक तकनीक का आगमन
- अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ जुड़ाव
- सरकारी राजस्व में वृद्धि

इस तरह अर्थव्यवस्था के विकास में FDI अहम भूमिका निभाता इसको आकर्षित करने के लिए भारत सरकार भी रियायती दरों पर भूमि, कर छूट आदि कार्यों को करती है।

कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

प्र 2(ब) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर टिप्पणी?

उ. खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य सभी लोगो तक, हर समय व गुणवत्ता युक्त खाद्य की पहुंच से लिया जाता है इसके लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 पारित किया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

प्रावधान — चुनौतियाँ — प्रभाव

प्रावधान – ग्रामीण क्षेत्रो में 75% व शहरी क्षेत्रो 50% लोगो को प्रतिमाह 5 किग्रा प्रति व्यक्ति अनाज पाने का अधिकार

- दाम चावल – 3 रु प्रतिकिग्रा, गेहूँ – 2 रु प्रति किग्रा. मोटा अनाज – 1 रु किग्रा प्रतिकिग्रा.
- आंगनवाड़ी परिवार की महिलाओं के नाम
- मातृत्व सहयोग गर्भवती महिला को 6000 रु आर्थिक मदद

चुनौतियाँ :) – कृषि मानसून पर निर्भरता कभी अधिकवर्षा, सूखा।

- भंडारण व वितरण की समस्या
- PDS में भ्रष्टाचार
- कृषि में पूंजी, आधुनिक तकनीक का अभाव आदि

सुझाव => कृषि मे नवीन तकनीक, सिंचाई ड्रिप सिंचाई

- ऋण सस्ता व सरल गमन
- भंडारण की उचित व्यवस्था। आदि

इस तरह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इससे संबंधित चुनौतियों को दूरकर प्रत्येक व्यक्ति तक खाद्य की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि कोरोना जैसी महामारी के समय खाद्यान्न की आपूर्ति हमेशा बनी रहे

प्रश्न संख्या | मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका (Mains Answer Sheet) | सफलता का प्रतीक द्वार...

प्रश्न 2(ii) म.प्र. में औद्योगिक विकास की संभावना

म.प्र. औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है किंतु म.प्र. में नवीन उद्योगों व पुराने उद्योगों की क्षमता में सुधार कर औद्योगिक विकास को गति दी जा रही

म.प्र. में औद्योगिक विकास की संभावनाएं देखे तो वह इस प्रकार

(1) कृषि के क्षेत्र => गेहूँ के उत्पादन में प्रदेश प्रथम सोयाबीन, चने आदि खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावना

(2) खनिज के क्षेत्र - हीरे के उत्पादन में प्रथम कोयला, तांबा, बाक्साइट, आदि को लेकर उद्योग स्थापित

(3) वनों के क्षेत्र => म.प्र. वनों के क्षेत्रफल में प्रथम, साल, सागोन, तेंदूपत्ते आदि को लेकर संबंधित उद्योग

(4) पर्यटन के क्षेत्र => ऐतिहासिक स्थल - भीमबेटका सांची
प्राकृतिक स्थल - पंचमढ़ी अमरकंटक
धार्मिक स्थल - महाकाल (उज्जैन), जैन स्थल
और यूनेस्को की विश्व धरोहर खजुराहो

सांची ओमकेश्वर

पर्यटन उद्योग की म.प्र. में अधिक संभावना

क्र-प => सरकार द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था।

=> SEZ की सुविधा।

- अवसंरचनात्मक निर्माण आदि

उपरोक्त के आधार पर अपार संभावना केवल ऊर्जा, विद्युत, जल, परिवहन आदि कमियों को दूर कर म.प्र. औद्योगिक रूप से विकसित किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका (Mains Answer Sheet)

कौटिल्य एकेडमी सफलता का प्रवेश द्वार

Q. 2(a) रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर लिखिये?

बैंक का मुख्य कार्य लोगो की जमा स्वीकार करना व उनको ऋण देना. भारत में यह कार्य RBI व व्यापारिक बैंको के माध्यम से किया जाता है

रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक के अंतर को निम्न प्रकार देख सकते

अंतर	रिजर्व बैंक	व्यापारिक बैंक
अर्थ	=> यह सभी बैंकों का बैंकर व देश की शीर्षस्थ संस्था	- यह बैंक RBI के नियंत्रण में कार्य यह एक इकाई
साख नियंत्रण	=> RBI अर्थव्यवस्था में साख व प्रसार संकुचन में नियंत्रण	- व्यापारिक बैंक साख सृजित करते है
कार्य	=> यह सरकार के बैंक के रूप में कार्य	- यह जनता के बैंकर है
उद्देश्य	=> सामाजिक कल्याण	- मुनाफा कमाना
नोट निर्गमन	=> नोट जारी करता	- यह अधिकार प्राप्त नहीं
विदेशी रिजर्व	=> संरक्षक होता	- संरक्षक नहीं होते

इस तरह हम दोनों के अंतर को देश में बैंकिंग प्रणाली के महत्व को समझ सकते हैं।

Q 2(H) प्रवसन के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए?

A.

प्रवसन का तात्पर्य किसी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसना है। प्रवसन यह अल्पकालिक व स्थायी दोनों हो सकता है।

प्रवसन के निर्धारक तत्वों को निम्न प्रकार से देख सकते

प्रवसन के निर्धारक तत्व →

- रोजगार ⇒ लोग रोजगार की तलाश गांव से शहर व देश से विदेश में प्रवसन
- मूलभूत आवश्यकता ⇒ स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
- आधुनिकतावादी प्रवृत्ति ⇒ लोग भौतिक सुख-सुविधाओं, उच्च जीवन स्तर के कारण
- सुख-शांति के लिए ⇒ गृहयुद्ध, आतंकवाद जैसी समस्याओं से निजात पाने के लि
- प्राकृतिक आपदा
- महामारी का प्रकोप ⇒ वर्तमान में मजदूरों का प्रवसन

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

उपरोक्त तत्व प्रकटन को प्रोत्साहित करते है इसको रोकने के लिए धर्मातीत विवाद की अवधारणा को साकारित करने की आवश्यकता है।

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

सफलता का प्रवेश द्वार...

Q4 (E) स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है इसके लाभों को लिखिये ?

स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, एक सड़क परिवहन योजना थी जो वर्ष 1999 में बनकर तैयार हुई इसमें दिल्ली, कोलकता, चेन्नई व मुम्बई को सड़क मार्ग से जोड़ा जिसकी लंबाई 5846 किमी है

इसके लाभों के बारे में चर्चा करें तो निम्न लाभ दिखाई देते –

- प्रमुख शहर व बंदरगाह परिवहन नेटवर्क से जुड़े
- → भारत के प्रमुख कृषि, औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्रों का संपर्क मार्ग स्थापित
- → आंतरिक व बाह्य व्यापार को बढ़ावा
- → लघु व बड़े उद्योगों का विकास हुआ
- → बाजार तक पहुँच सुनिश्चित होने से उत्पादन में वृद्धि
- → रोजगार सृजन
- → पूंजी निर्माण
- → औद्योगिक क्षेत्रों के आस-पास के गांवों, कस्बों का सामाजिक-आर्थिक विकास हुआ आदि
- → राष्ट्र की एकता व अखण्डता को बल

इस तरह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संपूर्ण भारत को एकीकृत कर आर्थिक विकास को गति प्रदान की यह गति अभी भी निरंतर जारी है।

Q 3(a) विकासशील देशों की समस्याओं का उल्लेख करो?

A. विकासशील देश उन देशों को कहते है जिनकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होता है तथा आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर, औद्योगिक विकास धीमा, निम्न जीवन स्तर आदि. भारत भी एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है जो विकसित देश बनने के लिए निरंतर तेज गति से विकास के मार्ग में अग्रसर है

विकासशील देशों की समस्याओं पर नजर डाले तो नि. समस्याएं नजर आती —

समस्याएं

आर्थिक समस्या | सामाजिक समस्या | राजनैतिक समस्याएं | प्रशासनिक समस्याएँ

आर्थिक समस्या => (1) कृषि की प्रधानता - विकासशील देशो की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान

(2) **पूंजी की कमी** => पूंजी के अभाव में औद्योगिक गतिविधियाँ कम, उत्पादन में कमी

बेरोजगारी => जनसंख्याअधिक, अवसरों की कमी कौशल अभाव आदि के कारण बेरोजगारी

औद्योगिकीकरण का अभाव => पूँजी व तकनीकी के अभाव के कारण औद्योगिक विकास की दर कम।

प्रतिव्यक्ति आय में कमी => प्रतिव्यक्ति आय निम्न जीवन स्तर निम्न

सामाजिक समस्याएँ => - परंपरावादी समाज
- शिक्षा का निम्न स्तर
- स्वच्छ जीवन स्तर का अभाव
- जनसहभागिता का अभाव

राजनीतिक समस्याएं => विकासशील देशों राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है
- लोग अपने राजनीतिक अधिकारों से अज्ञात
- कुशल विपक्ष का अभाव

प्रशासनिक समस्या => योग्य प्रशासकों का अभाव

- कुशल प्रशासकों के न होने से लोककल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन में गड़बड़ी
- केन्द्र - राज्य व गांव स्तर पर समन्वय का अभाव

अन्य समस्या → जनसंख्या अधिक गरीबी

- तकनीकी की कमी
- नवाचार का न होना आदि
- अवसंरचना का अभाव

उपरोक्त समस्याएँ विकासशील देशों के मार्ग में बाधाएँ है जिनको दूर करने का प्रयास प्रत्येक देश द्वारा किया जा रहा तथा औद्योगिकीकरण अवसंरचनात्मक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का विकास कर समावेशी विकास की ओर अग्रसर हो रहे भारत भी इसी मार्ग पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।

प्रश्न 3(ब) नीति आयोग की संरचना, उद्देश्य व कार्य बतें साथ ही नीति आयोग व योजना आयोग में अंतर

भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई यह एक थिंक टैंक की तरह कार्य करता है जो केंद्र व राज्य सरकार को क्रियात्मक नीतियों के निर्माण संबंधी सलाह देता है अर्थात यह एक सलाहकारी निकाय जो केंद्र व राज्यों के सहयोग से मिलकर बना।

नीति आयोग की संरचना को देखें तो वह निम्न है-

अध्यक्ष = प्रधानमंत्री जी
उपाध्यक्ष —
सीईओ
संचालन परिषद => इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल।
पूर्णकालिक सदस्य - 5
अंशकालिक सदस्य - 2

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका (Mains Answer Sheet)

सफलता का प्रवेश द्वार...

नीति आयोग के उद्देश्यों पर नजर डाले तो वह समझता है –

(क) यह विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण दिशा व रणनीतिक जानकारी देते

- मजबूत राष्ट्र के लिए सहकारी संघवाद को बढ़ावा

- यह नीतियों व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी, मूल्यांकन के साथ प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण व क्षमता निर्माण पर बल

- ग्राम स्तर पर योजनाओं को तैयार व उसे उच्च स्तर तक ले जाते

- उन वर्गों पर विशेष ध्यान देते है जो विकास से लाभान्वित नहीं हो सके।

- यह दीर्घावधि नीतियों व कार्यक्रमों का ढांचा तैयार कर इसकी निगरानी व मध्यावधि संशोधन

- आयोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, व्यवसायियों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिये ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता के अनुरूप सहायक प्रणाली बनायेगा।

योजना आयोग व नीति आयोग के अंतर को निम्नानुसार देख सकते है –

अंतर	योजना आयोग	नीति आयोग
- वित्तीय संदर्भ	- राज्यों हेतु फंड निर्धारण की शक्ति	- यह सलाहकारी संस्था फंड निर्धारण वित्त मंत्रालय
- राज्यों की भूमिका	- कम	- संचालन परिषद राज्यों की सक्रिय भूमिका
पूर्णकालिक अंशकालिक सदस्य	- 8 पूर्णकालिक - अंशकालिक नहीं	- 5 पूर्णकालिक - 2 अंशकालिक

इस तरह योजना आयोग की कमियों को देखते हुए नीति आयोग की स्थापना की गई जो देश को क्रियात्मक गतिविधियों में सलाह व सहकारी संघवाद को बढ़ावा देगी एवं गांव से लेकर केंद्र तक कार्यों व नीतियों को तैयार कर गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकारित किया जा सके

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

Qu 3(c) भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण विधियों को लिखिये?

RBI भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को कि गई थी जिसका कार्य नोटो का निर्गमन, सरकार का बैंकर, विदेशी विनिमय का नियंत्रण आदि कार्यों को करना साथ ही साख नियंत्रण की उसका मुख्य कार्य है।

साख नियंत्रण के लिए RBI निम्न विधियों को अपनाता है जो इस प्रकार

साख नियंत्रण की विधियां :

- मात्रात्मक नियंत्रण
  - रेपो रेट
  - रिवर्स रेपो रेट
  - CRR
  - SLR
  - खुले बाजार की क्रिया (OMO)
- गुणात्मक नियंत्रण
  - चयनित साख नियंत्रण
  - साख की राशनिंग
  - अधिकरण की योजना

मात्रात्मक नियंत्रण =>

रेपो रेट => बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए RBI, बैंकों को एक दर पर अल्पावधिक रूप से ऋण देता, तथा इस दर को बदल-बदल कर मुद्रा का प्रसार व संकुचन करता है

रिवर्स रेपो रेट => RBI प्रतिभूतियों को बेचकर एक दर पर वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है इसकी दर रेपो रेट से कम होती है

नगद आरक्षित अनुपात (CRR) => इसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक अपनी नगद जमाराशि का एक निश्चित भाग RBI के पास रखते

बैंक रेट => वह ब्याज दर पर RBI बैंकों को दीर्घावधिक रूप से ऋण देता

ओपन मार्केट ऑपरेशन => RBI अपनी प्रतिभूतियों को क्रय - विक्रय कर नियंत्रण

गुणात्मक नियंत्रण =>

चयनात्मक साख नियंत्रण - RBI, बैंकों के संबंध में कुछ नियम बनाते इसके अंतर्गत

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

कौटिल्य एकेडमी
सफलता का प्रवेश द्वार...

- ऋण देने में प्रतिबन्ध
- RBI की पूर्वानुमति के पश्चात ऋण

साख राशनिंग => RBI द्वारा निश्चित कि प्रत्येक बैंक को कितनी साख दी जायेगी

↳ बैंकों के साख निर्माण की शक्ति सीमित

प्राधिकरण की सीमा => दो करोड़ या उससे अधिक राशि देने पर RBI की अनुमति आवश्यक

उपरोक्त विधियों का प्रयोग कर RBI बाजार में मुद्रा का प्रसार या संकुचन कर साख का नियंत्रण कर वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने से रोकता तथा आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करता उदा. के रूप में वर्तमान कोरोना महामारी के समय RBI द्वारा ऋणों की दरों में कमी बाजार में मुद्रा प्रसार को सूचित करता है जो आर्थिक विकास में [illegible] होगा।